उत्तरांचल शासन कार्मिक विभाग

अधिसूचना

07 नवम्बर, 2002 ई0

सं0 1472 / कार्मिक -2 / 2002 - चूकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की घारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकृतन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो;

तथा चूकि, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और मृतपूर्व सैनिक) के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, उत्तर प्रदेश पुनर्गंडन अधिनियम, 2000 की घारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है;

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व रौनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, उत्तरांवल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्याधीन लागू रहेगा :-

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और मूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 १-संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्म-

- (1) यह आदेश उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश लोक शेवा (शारिरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और मृतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1983] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 कहलायेगा।
 - (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2-"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता राग्राम शंनानियों के आश्रित और मृतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 में जहां—जहां शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है, वहां—वहां वह शब्द "उत्तराचल" के रूप में पदा जायेगा।

> आज्ञा से, आलोक कुमार जैन्द्र सविव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India. The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1472/Ka-2/2002, dated November 07, 2002 for general information:

NOTIFICATION

November 11, 2002

No. 1472/Ka-2/2002--WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Government of Uttaranchal may by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as may be necessary or impediment;

AND WHEREAS, Uttar Pradesh Lok Seva (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and ex-Servicemen) Act. 1993 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000) the Governor is pleased to direct the Uttar Pradesh Public Service (reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and ex-Servicemen) Act 1993, shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order,

UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE, (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDENTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EXSERVICEMEN) ACT 1993] ADAPTATION & MODIFICATION ORDER, 2002

1-Short title and Commencement-

- (1) This order may be called Ultaranchal [The Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and ex-servicemen) Act 1993], Adaptation & Modification Order 2002.
 - (2) It shall come in to force at once.

2-The word "Uttar Pradesh" to be read "Uttaranchal"-

In the Ultar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and ex-Servicemen) Act, 1993 wherever the expression "Utlar Pradesh" occurs it shall be read as "Uttaranchal".

the second secon

By Order, ALOK KUMAR JAIN, Secretary.